

जल्द घोषित और लागू होगी मध्य प्रदेश की आई. टी. पॉलिसी

चर्चा में क्यों?

26 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने बताया कि मध्य प्रदेश की आईटी-आईटीईएस और ईएसडीएम नीति शीघ्र ही घोषित और लागू की जाएगी।

प्रमुख बंदि

- एमएसएमई मंत्री ने बताया कि इस नीति का लक्ष्य सभी कारकों का समावेश कर आईटी क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिये एक जीवंत तथा समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है।
- राज्य में अनुसंधान एवं विकास, नविश, रोजगार, नवाचार और उद्योगों के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने पर इस नीति में विशेष ध्यान दिया गया है।
- उन्होंने बताया कि 2023 के लिये मध्य प्रदेश की आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम नीति उद्योग जगत से विचार-विमर्श के विभिन्न सत्रों और विभिन्न राज्य की नीतियों की बेंचमार्क के पश्चात् बनाई गई है।
- नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रोत्साहन प्रदान कर और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम क्षेत्रों में नविश आकर्षित करना है। यह नीति विद्युत-अनुकूल वातावरण बनाने और उद्योगों के विकास के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने पर केंद्रित है।
- मंत्री सखलेचा ने बताया कि नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपए का नविश आकर्षित कर 2 लाख नई नौकरियाँ सृजित करना है।
- इसमें 10 मिलियन वर्गफुट आईटी, ईएसडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का निर्माण, राज्य भर में अत्याधुनिक आईटी पार्क, भवन, प्लग एंड प्ले स्पेस को आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम के लिये प्लग एंड प्ले और रेडी टू बिलड फैक्टोरियों शामिल कर बुनियादी ढाँचा खड़ा करने पर जोर दिया गया है।
- एमएसएमई मंत्री ने बताया कि ड्राफ्ट नीति निवीन विशेषताएँ परसतुत करती है, जो उद्योग के समक्ष आने वाली महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान भी सुझाएगी। ड्राफ्ट नीति में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिये CAPEX सहायता का विशेष प्रावधान प्रदान करके विश्व स्तरीय आईटी बुनियादी ढाँचा विकसित करने के प्रावधान शामिल हैं।
- नीति में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और वनिरिमाण (ईएसडीएम) क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है और पूंजी सब्सिडी कैपिंग को बढ़ाकर उनका समर्थन किया गया है।
- प्रारूप नीति में ईएसडीएम इकाइयों में नविश आकर्षित करना, स्वदेशी वनिरिमाण को बढ़ावा देना और एक मज़बूत आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना शामिल है।
- नीति विद्युत-अनुकूलन संचालन स्थापित करने में मदद करने के लिये करिये में सहायता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिये रोजगार सृजन सहायता प्रदान करती है।
- यह नीति टेस्टिंग, कैलब्रेशन प्रयोगशालाओं, गुणवत्ता प्रमाणन, पेटेंटिंग और स्टैंड अलोन शोध और विकास इकाइयों का समर्थन करने के लिये विभिन्न प्रोत्साहन के माध्यम से प्रतष्ठानों को सहायता प्रदान करके अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है।
- ड्राफ्ट नीति राज्य में विभिन्न प्रकार के डेटा सेंटर को आकर्षित करने पर जोर देती है। नीति में डेटा सेंटर इकाइयों के लिये विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रावधान विशेष रूप से तैयार किये गए हैं। नीति में अनुकूलित पैकेज के माध्यम से क्षेत्र में मेगा परियोजनाओं का समर्थन करने का भी प्रावधान है।
- नीति का लक्ष्य आईटी-ईएसडीएम क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिये एक जीवंत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिससे मध्य प्रदेश को आईटी के लिये एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।